

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग

देहरादून : दिनांक 30 मार्च, 2016

विषय :- शिवपुरी में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु अवस्थापना सुविधाओं यथा- कार्यालय भवन/स्टोर/डोरमैट्री/क्लास रूम/किचन/शौचालय/स्टाफ कक्ष इत्यादि का निर्माण किये जाने हेतु आगणन उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2146/दो-लेखा/2869/2015-16 दिनांक 18.03.16 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शिवपुरी में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु अवस्थापना सुविधाओं यथा- कार्यालय भवन/स्टोर/डोरमैट्री/क्लास रूम/किचन/शौचालय/स्टाफ कक्ष इत्यादि के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्तुत आगणन ₹ 210.71 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत ₹ 208.15 लाख (सिविल निर्माण कार्यों हेतु ₹ 181.57 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों हेतु ₹ 26.58 लाख) (जिसमें सर्विस टैक्स रु0 10.07 लाख की धनराशि भी सम्मिलित है) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रवाधानित बजट में प्रथम अनुपूरक से प्राविधानित धनराशि ₹ 80.00 लाख को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- कार्य आरम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या-400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015, शासनादेश सं0-474/XXVII(7)/2008 दि0-15-12-08 एवं शासनादेश संख्या-645/XXVII(1)/2015 दिनांक 04 जून, 2015, शासनादेश संख्या-1325/XXVII(1)/2015 दिनांक 16 नवम्बर, 2015 तथा शासनादेश संख्या-1336/XXVII(1)/2015 दिनांक 17 नवम्बर, 2015 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।
- कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाए।
- विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन केवल अपरीहार्य स्थिति की दशा में ही करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए।

9. यदि उक्त कार्य हेतु प्रथम चरण के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है, तो यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यदि प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में बचत है, तो उसे द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित कर लिया जाए।
10. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-5-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
11. अधिप्राप्ति कार्यों हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
12. कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।
13. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।
14. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-001-निदेशन तथा प्रशासन-15-प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों का व्यवसायिक प्रशिक्षण-25-लघु निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।
15. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-449(P)/XXVII(3)/2016 दिनांक 30.03.16 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 235 /VI-2/2016-52(1)16, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. महाप्रबन्धक, उ०प्र०राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, देहरादून।
6. उ०प्र०राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, देहरादून इकाई-1, देहरादून।
7. एन०आई०सी०, सचिवालय देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
अनुसचिव।